(c) whether Government propose to make comprehensive modifications in the draft plan document; and

(d) if so, the steps since initiated in this direction?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) to (d). The new Government which has only recently assumed office proposes to consider the Plan afresh.

जनजाति क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई परियोजनाएं

115. **श्री कृष्ण दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ढाई वर्षों में जनजाति क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी उपयोग की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 16 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमण और द्वीव में विशेष जनजाति उपयोजनाएं बनाई गई हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की वे सभी प्रशासनिक एकाईयां (अर्थात ब्लाक, ताल्लुक) सम्मिलित हैं जिनमें 50 प्रतिशत और इससे अधिक आबादी जनजातियों की है। जनजाति उप-योजना क्षेत्र 180 समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं में गठित किये गये हैं और क्षेत्र की क्षमता और लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अलग विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में सभी विकास क्षेत्र जैसे कृषि, जंगलात, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित है। जनजाति उप-योजना का वित्तीय प्रबन्ध राज्य योजना विशेष केन्द्रीय संस्थागत वित्त और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध निधि से किया जाता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए निधि का आवंटन और प्रयोग निम्न प्रकार से था:-

1977-78

	करोड़ रु०
राज्य योजनाओं से आवंटन	257.00
उपयोग किया गया	249.96
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	55.00
उपयोग किया गया	54.98

1978-79

राज्य योजनाओं से आवंटन	344.00
उपयोग किया गया	311.11
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	70.00
उपयोग किया गया (आंकड़े अधूरे है)	45.54

1979-80

राज्य योजनाओं से आवंटन	394.00
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	70.00

उद्योगों को वित्तीय सहायता

116. **श्री कृष्ण दत्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने देश में किन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या उसका ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या किन्हीं उद्योगों ने सहायता राशि का दुरुपयोग किया है और यदि हां तो उन उद्योगों के नाम क्या है और वह राशि कितनी है ?

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन): (क) से (ग) निश्चित विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है इस प्रकरण में जानकारी इकट्ठी करने में जो प्रयास किए जायेंगे उनके प्राप्त परिणाम तदनुरूपी नहीं होंगे।

Foreign Nationals without Passports

117. SHRI KRISHAN DUTT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be be pleased to state the number of foreign nationals in India, country-wise, who entered the country without passports during the last 2½ years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Commission Appointed to Examine case Against Shri Kanti Desai

118. SHRI V. N. GADGIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Commission appointed to examine the case against Shri Kanti Desai, son of former Prime Minister, Shri Morarji Desai has submitted its report; and

(b) if so, what are the findings of the Commission?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI ZAIL SINGH): (a) and (b). Shri Justice C. A. Vaidyalingam, a retired Judge of the Supreme Court, was appointed as Special Judge on 28-4-1979 to inquire whether any *Prima facie* case in respect of the charges (pertaining to the period after the Janata Government took charge in March, 1971) referred to in the Debate on the Motion that was adopted on 10-8-1978 in the Rajya Sabha, is established against the family members of the former Prime Minister, Shri Morarji Desai, and the former Home Minister, Shri Charan Singh, so as to justify a formal inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952. Shri Justice C. A. Vaidyalingam has submitted his report of inquiry on 25-1-1980 and it is under examination.

Demand for more powers to West Bengal

119. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported statement of the Chief Minister of West Bengal appearing in Statesman (Delhi Edition) dated 12th January, 1980 regarding more powers for State to maintain federal principle in the country; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Government have seen the press report in question.

(b) The Government have not yet had an opportunity to examine the matter and take a view thereon.

Complaints made by B.A.R.C. Officers' Association

120. SHRI R. K. MHALGI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bhabha Atomic Energy Centre Officers' Association made certain complaints about the difficult working conditions and certain management practices of the Department of Atomic Energy;

(b) if so, when and the details thereof; and

(c) what action have Government taken or propose to take thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Since its informal recognition in 1971, the Bhabha Atomic Research Centre Officers' Association has sent many representation/suggestions from time to time. These have dealt with working conditions in BARC and various other matters.